पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

स्मिता चंद्रमणि कुमार

बनाम

बिहार कॉलेज ऑफ फार्मेसी और अन्य

2024 का सिविल विविध क्षेत्राधिकार सं. 121

03 अप्रैल 2025

(माननीय न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार झा)

विचार के लिए मुद्दा

- क्याइजराई वाद को इस आधार पर विधिक रूप से खारिज किया जा सकता था कि उसे सुनवाई हेतु नियत या सूचीबद्ध नहीं किया गया था?
- क्या आदेश 21 नियम 106(3) के तहत सीमावधि लागू होती है, या इस मामले को धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत देखा जाना चाहिए?
- क्या देरी के आधार पर पुनर्स्थापन याचिका को खारिज करना मामले की परिस्थितियों में विधिक रूप से टिकाऊ था?

हेडनोट्स

इजराई वाद को खारिज करना त्रुटिपूर्ण था क्योंकि यह वाद कभी भी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किया गया था और लगातार नाजिर की रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु स्थगित किया गया था। चूंकि वर्तमान मामला सुनवाई हेतु नियत नहीं था, अतः तकनीकी रूप से इसेइजराई न्यायालय द्वारा खारिज नहीं किया जा सकता था। इसी कारण,इजराई वाद को पुनर्स्थापित करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 नियम 106 का प्रयोग नहीं किया जा सकता। यदि आदेश 21 नियम 106 वर्तमान मामले में लागू नहीं होता है, तो 30 दिनों की सीमावधि की बाध्यता समाप्त हो जाती है और ऐसी स्थिति में धारा 151 के प्रावधान लागू होते हैं। भले ही आवेदन में गलत प्रावधान का उल्लेख हो, यदि वहइजराई वाद की पुनर्स्थापना के लिए राहत मांगता है, तो उसे धारा 151 के अंतर्गत माना जाना चाहिए। (पैरा 12)

यदि डिक्रीधारी या उत्तरदायी की मृत्युइजराई कार्यवाही के दौरान हो जाती है, तो कार्यवाही समाप्त नहीं होती, बल्कि लंबित रहती है। (पैरा 15)

याचिका स्वीकार की जाती है। (पैरा 21)

न्याय दृष्टान्त

डामोदरन पिल्लई एवं अन्य बनाम साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड, (2005) 7 एस सी सी 300 : ए आई आर 2005 एस सी 3460; एस. पोंनुपंडियन बनाम सेल्वबाकियम, ए आई आर 2004 मद. 272; रीजनल मैनेजर एवं अन्य बनाम पवन कुमार दुबे, ए आई आर 1976 एस सी 1766; सेटेलमेंट निदेशक, आंध्र प्रदेश एवं अन्य बनाम एम.आर. अप्पाराव एवं अन्य, (2002) 4 एस सी सी 638; आयकर आयुक्त बनाम सन इंजीनियरिंग वर्क्स (प्रा.) लिमिटेड, (1992) 4 एस सी सी 363; अंबिका क्वारी वर्क्स एवं अन्य बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य, (1987) 1 एस सी सी 213; फॉर्मोसा प्लास्टिक्स कॉर्पोरेशन यूएसए बनाम अशोक चौहान एवं अन्य, 2016 एस सी सी ऑनलाईन डेल 3141; ड्यूट्श रैंको जी एम बी एच बनाम मोहन मूर्ति, 2010 एस सी सी ऑनलाइन डेल 4220; गुजरात राज्य बनाम रामप्रकाश पी. पुरी एवं अन्य, 1969 (3) एस सी सी 156; स्मिटा धिरा मिश्रा उर्फ धिरा देवी एवं अन्य बनाम मोहम्मद लैएक अहमद एवं अन्य, 2024 (1) पी एल जे आर 818; क्विन बनाम लिथेम, (1901) ए सी 495; रोजर शशुआ एवं अन्य बनाम मुकेश शर्मा एवं अन्य, ए आई आर 2017 एस सी 3166; वी. उतिरापथि बनाम अशरफ अली एवं अन्य, (1998) 3 एस सी सी 148

अधिनियमों की सूची

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908; सीमांकन अधिनियम, 1963

मुख्य शब्दों की सूची

कार्यपालन वाद; बहाली; डिफॉल्ट खारिजी; सीमावधि; आदेश 21 नियम 105; आदेश 21 नियम 106; धारा 151 सी.पी.सी; अंतर्निहित शक्तियाँ; प्रक्रियात्मक विधि; अवसान; नाजिर की रिपोर्ट

प्रकरण से उत्पन्न

मूल आदेश दिनांक 22.11.2023, मि. केस संख्या 54/2017, उप न्यायाधीश-द्वितीय, दानापुर द्वारा पारित, जिसके द्वारा कार्यपालन वाद संख्या 07/1991 की बहाली याचिका अस्वीकृत की गई।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

याचिकाकर्ता की ओर से: श्री अमित श्रीवास्तव, वरिष्ठ अधिवक्ता; श्री गिरीश पांडेय, अधिवक्ता;श्री सुनील कुमार तिवारी, अधिवक्ता; श्री ब्रजेश सहाय, अधिवक्ता

प्रतिवादी की ओर से: श्री रौशन, अधिवक्ता

(रिपोर्टर द्वारा हेडनोट्स तैयार किया: अमित कुमार मल्लिक, अधिवक्ता)

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2024 के सिविल विविध क्षेत्राधिकार संख्या-121

==========

स्मिता चंद्रमणि कुमार, पिता-स्वर्गीय अरुण प्रसाद, स्थायी निवासी,- श्री सत्य साई विद्या विहार की, 20, लेन नंबर 1, विजय नगर, थाना-रूपसपुर, पटना-800014, वर्तमान निवासी-एफ-1902, टावर-II, अशोक गार्डन, (स्वान मिल्स कम्पाउंड), केईएम अस्पताल के पास, टी. जे. रोड, सेवरी रोड, मुंबई-400015, महाराष्ट्र

... ... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार कॉलेज ऑफ फार्मेसी, द्वारा-अध्यक्ष सह निदेशक, बेली रोड, पटना-800014।

2.1. प्रतीक सोनी, वर्तमान में अध्यक्ष-सह-निदेशक, बिहार कॉलेज ऑफ फार्मेसी बेली रोड, पटना-800014

... ...प्रतिवादी/ओं

==========

उपस्थिति :

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री अमित श्रीवास्तव, वरिष्ठ अधिवक्ता
श्री गिरीश पांडे, अधिवक्ता
श्री सुनील कुमार तिवारी, अधिवक्ता
श्री ब्रजेश सहाय, अधिवक्ता

प्रतिवादीओं के लिए : श्री रोशन, अधिवक्ता

==========

गणपूर्ति : माननीय न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार झा

मौखिक निर्णय

दिनांक- : 03-04-2025

याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ-साथ प्रतिवादिओं के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुना।

2. याचिकाकर्ता द्वारा, वर्तमान याचिका दानापुर में विद्वान उप न्यायाधीश-द्वितीय द्वारा विविध वाद संख्या-54/2017 में पारित दिनांक 22.11.2023 के आदेश को रद्द करने हेतु दायर की गई है। जिसके द्वारा और जिसके तहत विद्वान उप न्यायाधीश ने इजराई वाद सं. 07/1991 के पुन:स्थापन के लिए अनुरोध को खारिज कर दिया।

3. संक्षेप में कहा जाए तो मामले के तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता की मां श्रीमती वेणु प्रसाद, पटना के बेली रोड स्थित एक संपत्ति की एकमात्र स्वामिनी थीं, जिसे प्रतिवादी संख्या 1 को किराएदार मानते हुए पट्टे पर दिया गया था। पट्टे की अवधि समाप्त होने के बाद शांतिपूर्ण और खाली कब्जे को सौंपने से प्रतिवादी संख्या 1 के इनकार करने और प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा किराया भुगतान में चूक के कारण श्रीमती वेणु प्रसाद ने बकाया किराया वसूलने और प्रतिवादी संख्या 1 को उसकी किराए पर दी गई संपत्ति से बेदखल करने के लिए दानापुर के विद्वान उप न्यायाधीश-1 की अदालत में स्वतव वाद संख्या 220/1981 दायर किया। प्रतिवाद पर, वाद को 19.03.1991 के निर्णय और डिक्री द्वारा याचिकाकर्ता की मां के पक्ष में डिक्री किया गया। याचिकाकर्ता की मां ने उक्त डिक्री के इजराई के लिए इजराई वाद संख्या 07/1991 दायर किया। उक्त इजराई मामले के लंबित रहने के दौरान श्रीमती वेणु प्रसाद की 19.07.2011 को कैंसर से मृत्यु हो गई। याचिकाकर्ता के पिता श्री अरुण प्रसाद ने उक्त इजराई मामला संख्या 07/1991 में पैरवी करने का प्रयास किया। हालांकि, उनकी गंभीर बीमारी के कारण उनका इलाज मुंबई में चल रहा था और 10.11.2014 को उनकी भी मृत्यु हो गई। वर्तमान याचिकाकर्ता भारतीय रिजर्व बैंक में अधिकारी के रूप में कार्यरत थी और मुंबई व अन्य स्थानों पर तैनात थी। वह बैंक की मुख्य महाप्रबंधक के पद से सेवानिवृत्त हुई। याचिकाकर्ता का बड़ा भाई 1991 से संयुक्त राज्य अमेरिका में काम कर रहा था। याचिकाकर्ता की छोटी बहन पहले अमेरिका में तैनात थी और उसके बाद वह अपने परिवार के साथ हैदराबाद में रह रही थी। याचिकाकर्ता को जून 2017 के महीने में किसी समय इजराई मामला संख्या 07/1991 के लंबित होने के बारे में पता चला, जब वह पटना गई थी और अपने माता-पिता के सामान की जांच कर रही थी। आगे की जांच करने पर, उसे पता चला कि स्वतव वाद संख्या 220/1981 का आदेश दिया गया था और 24.03.2017 को गैर-अभियोजन के लिए इजराई मामला संख्या 07/1991 को खारिज कर दिया गया था। उस समय, उसे

मुकदमे की घटनाओं के कालक्रम के बारे में भी पता चला। याचिकाकर्ता ने आगे जानकारी एकत्र की कि प्रतिवादी संख्या 1, अर्थात्, बिहार कॉलेज ऑफ फार्मेसी ने स्वतव अपील संख्या 140/1991 दायर करके स्वतव वाद संख्या 220/1981 के फैसले और डिक्री को चुनौती दी थी, जिसे दिनांक 12.07.2002 के आदेश द्वारा डिफ़ॉल्ट के लिए खारिज कर दिया गया था। दिनांक 22.07.2002 के आदेश को चुनौती देते हुए मामला संख्या 22/2005 दायर किया गया था और प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दायर इस विविध मामले को भी विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा दिनांक 23.04.2010 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। उक्त आदेश के विरुद्ध विविध अपील संख्या 464/2010 दायर की गई थी जिसे इस न्यायालय द्वारा दिनांक 05.04.2014 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया। याचिकाकर्ता को यह भी पता चला कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा कुछ रिट याचिकाएं भी दायर की गई थीं जिन्हें इस न्यायालय द्वारा डिफ़ॉल्ट रूप से खारिज कर दिया गया था। इसके अलावा, प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दायर विशेष अनुमति अपील (सिविल) संख्या 2962/1988 को भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 07.12.1988 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। कानूनी सलाह लेने के बाद याचिकाकर्ता ने 11.08.2017 को इजराई केस संख्या 07/1991 की बहाली के लिए याचिका दायर की। आगे यह भी पता चला कि विविध केस संख्या 54/2017 की सुनवाई हुई और विद्वान उप न्यायाधीश-II, दानापुर ने 22.11.2023 के आदेश के तहत इसे सीमा अवधि द्वारा वर्जित मानते हुए खारिज कर दिया। इस आदेश को इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई है।

4. याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अमित श्रीवास्तव ने जोरदार तर्क दिया कि विवादित आदेश टिकाऊ नहीं है क्योंकि इसे गलत विधिक सिद्धांतों को लागू करके और विद्वान इजराई न्यायालय के समक्ष तथ्यों और परिस्थितियों की सराहना किए बिना पारित किया गया है। श्री श्रीवास्तव प्रस्तुत करते हैं कि विद्वत इजराई न्यायालय ने इस तथ्य की सराहना नहीं की कि वाद नाजिर की रिपोर्ट के लिए आ रहा है और जिस तिथि को इजराई वाद संख्या 07/1991 खारिज किया गया था, और फिर से नाजिर की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक तिथि निर्धारित की गई थी और मामले को सुनवाई के लिए नहीं रखा गया था। खारिज करने की तारीख यानी 24.03.2017 पर सुनवाई/सुनवाई के लिए तारीख तय नहीं की गई थी। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि दिनांक 09.09.2014 को और उससे पहले विभिन्न तिथियों के ऑर्डर शीट के प्रासंगिक हिस्से को पुरी तरह पढ़ने से पता चलेगा और यह प्रदर्शित होगा कि पैरवी डिक्री धारक की ओर से की जा रही थी। इसके बाद, 11.02.2015 से 21.02.2017 तक, डिक्री धारक ने हाज़ीरी दाखिल नहीं की, परंतु यह स्पष्ट है कि इन सभी तिथियों पर, मामला नाजिर की रिपोर्ट के लिए स्थगित किया जा रहा था। निर्णायक तिथि पर भी, अर्थात 24.03.2017, को मामला नाजिर की रिपोर्ट

के लिए सामने आया। श्री श्रीवास्तव दोहराते हैं कि दानापुर के विद्वान उप न्यायाधीश ने उक्त इजराई मामले संख्या 07/1991 को भी सुनवाई/सुनवाई के लिए निर्धारित नहीं किया था। इसके बाद, श्री श्रीवास्तव ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 नियम 105 (संक्षेप में 'संहिता') का उल्लेख किया, जिसमें यह प्रावधान है कि जिस न्यायालय के समक्ष संहिता के आदेश 21 के किसी भी नियम के तहत आवेदन लंबित है, वह न्यायालय आवेदन की सुनवाई हेतु एक तारीख तय कर सकता है और जहां निर्धारित तिथि या किसी अन्य तिथि पर सुनवाई स्थगित की जा सकती है और जब मामला सुनवाई के लिए बुलाया जाता है तो आवेदक उपस्थित नहीं होता है, तो न्यायालय एक आदेश दे सकता है कि आवेदन खारिज कर दिया जाए। इस प्रकार, श्री श्रीवास्तव प्रस्तुत करते हैं कि विद्वान उप न्यायाधीश-II, दानापुर ने संहिता के आदेश 21 नियम 105 (1) और (2) के प्रावधानों का पालन नहीं किया। इस कारण से संहिता के आदेश 21 नियम 106 (3) के प्रावधान, इजराई वाद संख्या 07/1991 के तथ्यों और परिस्थितियों से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हैं। विद्वान उप न्यायाधीश-II, दानापुर, जिन्होंने विवादित आदेश पारित किया है, यह अभिनिर्धारित करने में गलत थे कि वाद के तथ्यों और परिस्थितियों में संहिता का आदेश 21 नियम 106 लागू होता है। इस कारण हेतु, विद्वान उप न्यायाधीश-II द्वारा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों ***दामोदरन पिल्लई और अन्य बनाम साउथ इंडियन बैन लिमिटेड (एस. सी. सी. (2005) 7- 300) : ए. आई. आर. 2005 एस. सी. 3460*** में रिपोर्ट किया गया, और ***एस. पोन्नुपंडियन बनाम सेल्वाबकियाम, ए. आई. आर. 2004 मद्रास- 272*** में रिपोर्ट किया गया, के वाद में निर्णयके अनुपात पर भारी झुकाव दिखाया गया, यह पूरी तरह से गलत धारणा है और कानून की नजर में अस्वीकार्य है। विद्वान उप न्यायाधीश कानून के इस स्थापित सिद्धांत को समझने में चूक गए कि इस प्रकार से तय किए गए मामले के अनुपात पर उस विशेष मामले के तथ्यों के आधार पर विचार किया जाना चाहिए और उसे लागू किया जाना चाहिए तथा तथ्यों में कोई मामूली अंतर भी अनुपात निर्णय के सिद्धांत को लागू करने और लागू करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। विद्वान वरिष्ठ वकील ***क्षेत्रीय प्रबंधक एवं अन्य बनाम पवन कुमार दुबे*** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला देते हैं, जिसकी रिपोर्ट ***एआईआर 1976 एससी 1766*** में दी गई थी, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने पैराग्राफ संख्या 7 में माना था कि यह नियम है जो किसी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के लिए कानून के आवेदन से निकाला जा सकता है, जो उसका अनुपात निर्णय बनाता है, न कि तथ्यों पर आधारित कोई निष्कर्ष जो समान प्रतीत हो सकता है। एक अतिरिक्त या अलग तथ्य दो मामलों में निष्कर्षों के बीच बहुत बड़ा अंतर पैदा कर सकता है, भले ही प्रत्येक मामले में समान तथ्यों पर समान सिद्धांत लागू किए गए हों। ***क्षेत्रीय प्रबंधक एवं अन्य*** के निर्णय का हवाला देते हुए। ***(उपर्युक्त), निपटान निदेशक ए.पी. एवं अन्य बनाम एम.आर. अप्पाराव एवं अन्य, (2002) 4 एससीसी***

638 में रिपोर्ट किया गया, आयकर आयुक्त बनाम मेसर्स सन इंजीनियरिंग वर्क्स (पी.) लिमिटेड, (1992) 4 एससीसी 363 में रिपोर्ट किया गया और अंबिका क्वारी वर्क्स एवं अन्य बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य, (1987) 1 एससीसी 213 में रिपोर्ट किया गया, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त प्राधिकारियों के माध्यम से घोषित किया कि यह स्पष्ट है कि किसी निर्णय का अनुपात पूर्ववर्ती मूल्य रखता है और न्यायालय के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्णय पर विचार करे, क्योंकि उसमें प्रस्तुत तथ्य और वह संदर्भ जिसमें प्रश्न उठे थे और कानून घोषित किया गया है, को ध्यान में रखा गया है। निर्णय को संपूर्णता में पढ़ना भी आवश्यक है और यदि कोई सिद्धांत निर्धारित किया गया है, तो उस पर मामले में विचार के लिए उठे प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाना चाहिए। किसी से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वह संदर्भ से हटकर निर्णय के किसी शब्द या वाक्य को उठाए और निर्णय के अनुपात को समझे, जिसका पूर्ववर्ती महत्व है। इसके अलावा, जिस न्यायालय के समक्ष कोई प्राधिकरण प्रस्तुत किया जाता है, उसे उसमें क्या निर्णय लिया गया है, इस पर विचार करना आवश्यक है, लेकिन यह नहीं कि न्याय-तर्क प्रक्रिया का पालन करके क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है।

5. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे कहा कि विद्वान उप न्यायाधीश ने यह नहीं समझा कि मामले के तथ्य, जिन पर भरोसा किया गया है, वर्तमान मामले के तथ्यों से स्पष्ट रूप से भिन्न हैं। ***दामोदरन पिल्लई एवं अन्य*** (उपर्युक्त) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद संख्या 8 में संहिता के आदेश 21 नियम 105 के प्रावधानों को स्पष्ट रूप से दर्ज किया था। उक्त निर्णय इस आधार और तथ्य पर आधारित था कि इजराई मामला जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचारार्थ आया था, अर्थात इजराई मामला संख्या 234/1988, सुनवाई के लिए निर्धारित किया गया था और इसे 01.11.1990 को चूक के कारण खारिज कर दिया गया था। लेकिन वर्तमान इजराई मामला संख्या 07/1991 को कभी भी सुनवाई के लिए निर्धारित नहीं किया गया, बल्कि इसे नजीर की रिपोर्ट के लिए 24.03.2017 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इसलिए, वर्तमान मामले के तथ्यों में ***दामोदरन पिल्लई एवं अन्य*** (उपर्युक्त) के अनुपात की कोई प्रयोज्यता नहीं हो सकती। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे कहा कि एक बार यह स्पष्ट हो जाने पर कि इजराई याचिका को संहिता के आदेश 21 नियम 105(2) के प्रावधान को लागू करके खारिज नहीं किया जा सकता था, संहिता के आदेश 21 नियम 106 के तहत बहाली खंड की कोई आवश्यकता नहीं हो सकती। इसलिए गैर-अभियोजन के आधार पर खारिजी को रद्द करने के लिए दायर याचिका पर विलंब की माफी या सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 की प्रयोज्यता का कोई प्रश्न नहीं उठता।

6. श्री श्रीवास्तव आगे यह बताते है कि,इसी तरह का मुद्दा दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ के समक्ष ,***फॉर्मोसा प्लास्टिक कॉर्पोरेशन यू. एस. ए. बनाम अशोक चौहान और अन्य (एस.एस.सी-2016,आनलाइन दिल्ली -3141*** में रिपोर्ट किया गया) के वाद में आया, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि दामोदरन पिल्लई (उपर्युक्त) निस्संदेह इस प्रस्ताव के लिए एक प्राधिकरण है कि जहां एक इजराई आवेदन सुनवाई के लिए निर्धारित किया गया है और आवेदक उपस्थित नहीं होता है, न्यायालय को इसे खारिज करने का अधिकार है और यदि पुनर्स्थापना के लिए आवेदन निर्धारित समय के भीतर नहीं किया जाता है, तो यह वर्जित है। इसके अलावा, ***डयुशे रैंको जी. एम. बी. एच. बनाम मोहन मूर्ति एस. सी. सी. 2010 में. ऑनलाइन दिल्ली-4220*** में रिपोर्ट किए गया) के वाद का उल्लेख करते हुए, जिसमें यह कहा गया है कि चूंकि इजराई याचिका सुनवाई के लिए निर्धारित नहीं की गई थी, इसलिए इसे चुक रूप में खारिज नहीं किया जाना चाहिए था और परिणामस्वरूप डिवीजन बेंच ने कहा कि इससे पहले चुनौती दी गई इजराई याचिका को खारिज करने के आदेश को इजराई कार्यवाही को खारिज करने के लिए एक के रूप में नहीं माना जा सकता था और यह उस तरह का आदेश था, जिसे डिवीजन बेंच ने ***डयुशे रैंको जी. एम. बी. एच.*** (उपर्युक्त) में दिमाग में रखा था और ***दामोदरन पिल्लई*** (उपर्युक्त) द्वारा कवर नहीं किया गया था। इस प्रकार, खंड पीठ ने ***फॉर्मोसा प्लास्टिक कॉर्पोरेशन यू. एस. ए.*** (उपर्युक्त) में निर्णय दिया कि संहिता की धारा 151 के तहत खारिजी आदेश को वापस लेने के लिए आवेदन बनाए रखने योग्य था और यह निर्णय लेना विद्वान एकल न्यायाधीश का काम था कि क्या अपीलार्थी ने बर्खास्तगी के आदेश को दरकिनार करने की मांग हेतु संहिता की धारा 151 के तहत अंतर्वर्ती आवेदन दाखिल करने में देरी के कारण का पर्याप्त खुलासा किया था। इस प्रकार, श्री श्रीवास्तव प्रस्तुत करते हैं कि विद्वत उप न्यायाधीश ने एक निष्कर्ष दर्ज करते हुए कहा कि इजराई मामले की पुनर्स्थापना के लिए याचिकाकर्ता का आवेदन सीमा द्वारा वर्जित था, जिसे परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत क्षमा आवेदन दायर करके भी ठीक नहीं किया जा सकता था, सही नहीं है और विद्वत उप न्यायाधीश को वाद के इस पहलू को ध्यान में रखना चाहिए था कि इजराई याचिका को सुनवाई के लिए स्थगित या सुनवाई के लिए निर्धारित नहीं किया गया था और इस कारण से संहिता के आदेश 21 नियम 105 (2) के तहत खारिज नहीं किया जा सकता था।

7. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे कहा कि यह अच्छी तरह से स्थापित कानून है कि संहिता के प्रावधान प्रकृति में प्रक्रियात्मक हैं और इस तरह के प्रक्रियात्मक कानून न्याय के कारण को आगे बढ़ाने के लिए हैं, न कि उसे पराजित करने के लिए। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने ***गुजरात राज्य बनाम रामप्रकाश पी. पुरी और अन्य तथा गुजरात राज्य बनाम सतु ख्यालदास और अन्य*** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला दिया, जिसकी रिपोर्ट ***1969 (3) एससीसी 156*** में दी गई थी, जिसमें यह माना गया है कि

प्रक्रिया को कानून की दासी के रूप में वर्णित किया गया है, न कि कानून की मालकिन के रूप में, जिसका उद्देश्य न्याय के कारण की सेवा करना और उसे सुविधाजनक बनाना है, न कि उसे नियंत्रित या बाधित करना।

8. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे कहा कि ***दामोदरन पिल्लई*** (उपर्युक्त) के तथ्य वर्तमान मामले से और भी भिन्न हैं। ***दामोदरन पिल्लई*** (उपर्युक्त) में, विद्वान अधिवक्ता जो उस मामले में उपस्थित थे, उन्हें इजराई मामले की अंतिम सुनवाई की तारीख का ज्ञान था, जो उक्त निर्णय का विषय था। इसके अलावा, यह स्वीकार किया जाता है कि इजराई मामला 01.11.1990 को चूक के कारण खारिज कर दिया गया था और बहाली आवेदन 04.04.1998 को दायर किया गया था, अर्थात, खारिज होने के लगभग साढ़े सात साल बाद, जिसमें तत्काल मामले में, इजराई मामले को 24.03.2017 को गैर-अभियोजन के लिए खारिज कर दिया गया था और बहाली याचिका 11.08.2017 को दायर की गई थी। विद्वान उप न्यायाधीश द्वारा ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं निकाला गया है कि आवेदक की ओर से इजराई वाद संख्या 7/1991 में उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को 24.03.2017 को तारीख तय होने के बारे में कोई जानकारी थी। बल्कि यह दर्ज किया गया है कि 06.12.2014 के बाद से कोई पैरवी नहीं की गई है। याचिकाकर्ता को उक्त इजराई वाद संख्या 7/1991 की तारीखों के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी क्योंकि उसके पिता अपने जीवनकाल में उक्त मामले की देखभाल कर रहे थे। इस प्रकार, याचिकाकर्ता को 24.03.2017 को या उससे पहले उक्त इजराई वाद की किसी भी तारीख के बारे में कोई जानकारी होने का कोई अवसर नहीं था। इस कारण से, कोड का आदेश 21 नियम 106 (3) भी याचिकाकर्ता के बचाव में आएगा क्योंकि याचिकाकर्ता की स्थिति एक ऐसे व्यक्ति के समान थी जिसे बर्खास्तगी का कोई नोटिस विधिवत नहीं दिया गया है और उसने अपने ज्ञान की तारीख से 30 दिनों के भीतर बहाली के लिए आवेदन दायर किया था। इस प्रकार, विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि 22.11.2023 का आरोपित आदेश रद्द करने योग्य है और इजराई मामला संख्या 7/1991 को अपनी मूल फ़ाइल में बहाल करने योग्य है क्योंकि आरोपित आदेश याचिकाकर्ता के इजराई मामला संख्या 7/1991 की बहाली की मांग करने के कानूनी, वैध और वैध अधिकार को पराजित नहीं कर सकता है। विद्वान वकील आगे ***श्रीमती धीरा मिश्रा उर्फ धीरा देवी और अन्य बनाम मो. लाइक अहमद एवं अन्य, 2024 (1) पीएलजेआर 818*** के मामले में इस न्यायालय के एक निर्णय का उल्लेख करते हैं। में रिपोर्ट किया गया, जिसमें इस न्यायालय ने पाया कि डिक्री धारकों की परेशानियां कम नहीं हुई हैं और इजराई कार्यवाही का उपयोग निर्णय-ऋणियों द्वारा दंड से मुक्त होकर किया जा रहा है जो इजराई कार्यवाही को विफल करने के लिए हर प्रावधान का अपने लाभ के लिए पूरी तरह से शोषण करते हैं जिससे पूरी प्रक्रिया एक तमाशा लगती है और अदालतें बेईमान वादियों के जाल में अनजाने उपकरण बन जाती हैं। इस प्रकार, श्री श्रीवास्तव ने प्रस्तुत किया कि डिक्री

के इजराई का फल डिक्री धारक को उपलब्ध कराया जाना चाहिए और यदि विवादित आदेश को रद्द नहीं किया जाता है, तो याचिकाकर्ता को अपूरणीय क्षति होगी।

9. प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री रौशन ने दृढ़तापूर्वक तर्क दिया कि आरोपित आदेश में कोई कमी नहीं है और इसमें इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। सर्वप्रथम, श्री रौशन ने प्रस्तुत किया कि वह ***दामोदरन पिल्लई*** (उपर्युक्त) के निर्णय पर अपना पूर्ण भरोसा रखते हैं और प्रस्तुत करते हैं कि यदि चूक के लिए आवेदन को खारिज करने का आदेश पारित किया गया है, तो उसकी बहाली के लिए आवेदन उक्त आदेश की तिथि से 30 दिनों के भीतर दायर किया जाना चाहिए, उसके बाद नहीं। इस कारण से, जिस तिथि को डिक्री धारक को इजराई याचिका को खारिज करने के आदेश का ज्ञान प्राप्त हुआ, वह पूरी तरह से अप्रासंगिक है। विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता का मामला पूरी तरह से समय सीमा से बाधित है। डिक्री धारक 06.12.2014 से *पैरवी* छोड़ चुका है और यह भी स्पष्ट है कि डिक्री धारक की मृत्यु वर्ष 2011 में हो गई थी, लेकिन इजराई मामले में उसके कानूनी प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड पर लाने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए। यहां तक कि मूल निर्णय ऋणी की मृत्यु वर्ष 2002 में हो गई थी, लेकिन मृतक निर्णय ऋणी के प्रतिस्थापन के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए। यहां तक कि मृतक/डिक्री धारक के नाम पर विविध मामला दायर किया गया था और इस मामले में डिक्री धारक या निर्णय ऋणी के कानूनी प्रतिनिधियों को लाने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए। यदि इजराई मामला आवेदक की गैरहाजिरी और रुचि की कमी के कारण खारिज कर दिया गया था, तो उक्त मामले को संहिता के आदेश 9 नियम 4 के तहत भी बहाल नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने माना है कि मामले को संहिता के आदेश 21 नियम 106 के तहत दायर किया जाना आवश्यक था और संहिता के आदेश 21 के नियम 106 के आवश्यक तत्वों को याचिकाकर्ता द्वारा संतुष्ट किया जाना आवश्यक था और विद्वान ट्रायल कोर्ट सही ढंग से इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि याचिकाकर्ता का बहाली आवेदन समय सीमा से टकराया था और इसे सही ढंग से खारिज कर दिया गया था। यदि 30 दिनों की समय सीमा पार हो गई थी तो देरी की कोई माफी नहीं हो सकती थी। विद्वान वकील याचिकाकर्ता के प्रार्थना भाग का संदर्भ देते हैं और प्रस्तुत करते हैं कि इजराई मामले को खारिज करने के आदेश को चुनौती नहीं दी जा सकती है। यह वह आदेश है जिसके द्वारा इजराई मामले की बहाली की मांग करने वाले विविध मामला संख्या 54/2017 को समय बीत जाने के कारण खारिज कर दिया गया था, जिसे इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई है। इस कारण से, याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत तर्क इजराई मामले को खारिज करने के खिलाफ है और इसे विविध मामले को खारिज करने के खिलाफ याचिकाकर्ता के कारण को

आगे बढ़ाने वाला नहीं कहा जा सकता है। इस प्रकार, विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान याचिका में कोई योग्यता नहीं है और इसे खारिज किया जाना चाहिए।

10. मैंने पक्षों के प्रतिद्वंदी प्रस्तुतिकरण पर विचारपूर्वक विचार किया है और अभिलेख का अवलोकन किया है।

11. इस न्यायालय के समक्ष मुद्दा यह है कि क्या विद्वान अधीनस्थ न्यायाधीश यह अभिनिर्धारित करने में सही था कि इजराई वाद संख्या 7/1991 की पुनर्स्थापना के लिए उसके समक्ष लाई गई याचिका को दिनांक 24.03.2017 के आदेश को दरकिनार करके सीमा द्वारा वर्जित किया गया था? आवेदक की गैर-उपस्थिति के लिए इजराई वाद को खारिज करने का प्रावधान संहिता के आदेश 21, नियम 105 के तहत किया गया है जो निम्नानुसार हैः –

> ***"105. आवेदन की सुनवाई-*** *(1) वह न्यायालय, जिसके समक्ष इस आदेश के पूर्वगामी नियमों में से किसी के अधीन एक आवेदन लंबित है, आवेदन की सुनवाई के लिए एक दिन निर्धारित कर सकता है।*
> *(2) जहां नियत दिन या किसी अन्य दिन जिस तक सुनवाई स्थगित की जाए, जब मामला सुनवाई के लिए बुलाया जाता है, आवेदक तब उपस्थित नहीं होता है, तो न्यायालय आदेश दे सकता है कि आवेदन को खारिज कर दिया जाए।*
> *(3) जहाँ आवेदक उपस्थित होता है और विरोधी पक्ष जिसे न्यायालय द्वारा सुचना दी गई है, उपस्थित नहीं होता है, न्यायालय आवेदन को एकतरफा सुन सकता है और ऐसा आदेश पारित कर सकता है जो वह उचित समझे।*

इसके बाद, संहिता के आदेश 21 नियम 106 में एकतरफा आदेश आदि को अलग करने का प्रावधान है, जो निम्नानुसार हैः-"

> ***''106. एकपक्षीय रुप से पारित आदेशो, आदि का अपास्त किया जाना*** *- (1) आवेदक, जिसके विरुद्ध नियम 105 उपनियम (2), , के तहत आदेश दिया गया है या विरोधी पक्ष जिसके विरुद्ध उस नियम के उपनियम (3) के अधीन या नियम- 23 के उपनियम (1) के अधीन एकपक्षीय आदेश पारित किया गया है, आदेश को दरकिनार करने के लिए न्यायालय में आवेदन कर सकता है, और यदि वह न्यायालय को संतुष्ट करता है कि आवेदन की सुनवाई के लिये पुकार होने पर उसके गैर-उपस्थिति के लिए पर्याप्त कारण था, तो न्यायालय खर्चो या अन्य बातो के बारे में ऐसे निबंधनों पर जो वह उचित समझे, और आवेदन की आगे की सुनवाई के लिए एक दिन निर्धारित करेगा।*

(2) उप-नियम (1) के अधीन आवेदन पर कोई आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि आवेदन की सूचना की तामील दूसरे पक्ष को नहीं दी गई हो।

(3) उप-नियम (1) के अधीन आवेदन आदेश की तारीख से तीस दिनों के भीतर किया जाएगा, या जहां, एक तरफा आदेश की दशा में, नोटिस विधिवत रूप से जारी नहीं किया गया था, उस तारीख से तीस दिनों के भीतर, जब आवेदक को आदेश की जानकारी थी।

12. वर्तमान वाद में, विद्वत विचारण न्यायालय के आदेश पत्र के अवलोकन से पता चलता है कि इजराई वाद संख्या 7/1991 नाजिर की रिपोर्ट के लिए स्थगित कर दिया गया था। इस अवधि के दौरान, वाद को सुनवाई के लिए कभी स्थगित नहीं किया गया था या सुनवाई के लिए कभी निर्धारित नहीं किया गया था जो आदेश 21 नियम 105 (2) के तहत आवश्यकताओं में से एक है। आवेदक की गैर-उपस्थिति के कारण इजराई आवेदन को खारिज करने के लिए, वाद को सुनवाई के लिए निर्धारित किया जाना आवश्यक है और गैर-उपस्थिति के आधार पर खारिज करने के लिए यह अनिवार्य है। चूंकि इजराई वाद संख्या 7/1991 का वर्तमान वाद सुनवाई के लिए निर्धारित नहीं किया गया था या 24.03.2017 को सुनवाई के लिए निर्धारित नहीं किया गया था, इसलिए तकनीकी रूप से इसे विद्वान इजराई न्यायालय द्वारा खारिज नहीं किया जा सकता था। इस कारण से, इजराई की बहाली के लिए संहिता के आदेश 21 नियम 106 का कोई आवेदन नहीं हो सकता है। यदि आदेश 21 नियम 106 वर्तमान मामले के तथ्यों में लागू नहीं होता है, तो बहाली आवेदन दायर करने के लिए 30 दिनों की सीमा समाप्त हो जाती है और ऐसी परिस्थितियों में, संहिता की धारा 151 के प्रावधान लागू होंगे। भले ही आवेदन गलत प्रावधान का उल्लेख करते हुए दायर किया गया हो, लेकिन इजराई की बहाली के मामले में राहत की मांग को संहिता की धारा 151 के तहत एक आवेदन के रूप में माना जाना चाहिए।

13. उपरोक्त दायरे से आगे बढ़ते हुए, यह स्पष्ट हो जाता है कि विद्वत विचारण न्यायालय का दृष्टिकोण शुरू से ही त्रुटिपूर्ण था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ***दामोदरन पिल्लई*** (उपर्युक्त) वाद में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि परिसीमा अधिनियम की धारा-5 के अधीन एक आवेदन संहिता के आदेश 21 के अधीन उत्पन्न होने वाली कार्यवाही में बनाए रखने योग्य नहीं है और इसने आगे अभिनिर्धारित किया कि परिसीमा अधिनियम की धारा-5 के अधीन एक आवेदन भी बनाए रखने योग्य नहीं था। लेकिन ***दामोदरन पिल्लई*** (उपर्युक्त) के तथ्य काफी अलग हैं। इजराई याचिका संख्या 234/1988 को सुनवाई हेतु स्वीकार किया गया था और उसके बाद इसे 01.11.1990 को चुक के कारण खारिज कर दिया

गया था। परंतु वर्तमान वाद में, इजराई वाद संख्या 7/1991 कभी भी सुनवाई के लिए निर्धारित नहीं किया गया था और इसे 24.03.2017 को चुक के कारण खारिज कर दिया गया था। इसलिए, वर्तमान वाद में, ***दामोदरन पिल्लई*** (उपर्युक्त) के अनुपात को लागू करने के लिए, तथ्य अलग हैं।

14. मैं याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील से कानून के इस प्रस्ताव के बारे में पूरी तरह सहमत हूँ कि किसी भी निर्णय का अनुपात उस मामले के तथ्यों की पृष्ठभूमि में समझा जाना चाहिए। ***क्विन बनाम लेथम*** में, ***(1901) एसी 495*** में रिपोर्ट किया गया, यह माना गया है कि एक मामला केवल इस बात के लिए एक प्राधिकार है कि वह वास्तव में क्या निर्णय लेता है, न कि उससे तार्किक रूप से क्या निकलता है। ***रोजर शशौआ और अन्य बनाम मुकेश शर्मा और अन्य*** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, ***एआईआर 2017 एससी 3166*** में रिपोर्ट किया, पैराग्राफ नं. 51 से 54 में से निम्नांकित निर्णय दिए गए:-

> *"**51.** इस समय, हम इस मुद्दे पर विचार करना आवश्यक समझते हैं कि क्या शशौआ सिद्धांत बाल्को और एनरकोन (इंडिया) लिमिटेड (उपर्युक्त) का अनुपात निर्णायक है और हम पूर्णता के लिए ऐसा करने का इरादा रखते हैं। कानून में यह अच्छी तरह से स्थापित है कि प्रत्येक मामले के अनुपात निर्णायक को सही ढंग से समझा जाना चाहिए। क्षेत्रीय प्रबंधक बनाम पवन कुमार दुबे में, तीन न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला सुनाया:*
>
> > *"7. ... यह नियम कानून के तथ्यों और परिस्थितियों के आवेदन से निष्कर्षित होता है जो मामले का अनुपात निर्णायक होता है, न कि तथ्यों पर आधारित कोई निष्कर्ष जो समान प्रतीत हो सकता है। एक अतिरिक्त या अलग तथ्य दो मामलों में निष्कर्षों के बीच बहुत बड़ा अंतर पैदा कर सकता है, भले ही प्रत्येक मामले में समान तथ्यों पर समान सिद्धांत लागू किए गए हों। "*
>
> ***52.** डायरेक्टर ऑफ सेटलमेंट्स, ए.पी. और अन्य बनाम एम.आर. अप्पाराव और अन्य में, एक अन्य तीन न्यायाधीशों की पीठ ने इस अवधारणा से निपटते हुए कि क्या कोई निर्णय "घोषित कानून" है, टिप्पणी की:*
>
> > *"7. ... लेकिन जो बाध्यकारी है वह निर्णय का अनुपात है, न कि तथ्यों का कोई निष्कर्ष। यह न्यायालय के समक्ष प्रश्नों के प्रकाश में, निर्णय को समग्र रूप से पढ़ने पर पाया गया सिद्धांत है जो अनुपात बनाता है, न कि कोई विशेष शब्द या वाक्य। यह*

निर्धारित करने के लिए कि क्या कोई निर्णय "घोषित कानून" है, इसे कानून नहीं कहा जा सकता है जब रियायत पर एक बिंदु का निपटारा किया जाता है और जो बाध्यकारी है वह निर्णय के अंतर्निहित सिद्धांत है। न्यायालय के निर्णय को उन प्रश्नों के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए जो उस मामले में विचार के लिए उठे थे जिसमें निर्णय दिया गया था।

53. *इस संदर्भ में, आयकर आयुक्त बनाम सन इंजीनियरिंग वर्क्स (पी) लिमिटेड का एक अंश बिल्कुल उपयुक्त होगा:*

"39. ... इस न्यायालय के निर्णय से एक शब्द या वाक्य को विचाराधीन प्रश्न के संदर्भ से अलग करके इस न्यायालय द्वारा घोषित पूर्ण 'कानून' मानना न तो वांछनीय है और न ही अनुमेय है। निर्णय को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए और निर्णय से टिप्पणियों पर इस न्यायालय के समक्ष मौजूद प्रश्नों के प्रकाश में विचार किया जाना चाहिए। इस न्यायालय का निर्णय उस मामले में शामिल प्रश्नों से प्रभावित होता है जिसमें इसे प्रस्तुत किया जाता है और बाद के मामले में निर्णय को लागू करते समय, न्यायालयों को इस न्यायालय के निर्णय द्वारा निर्धारित वास्तविक सिद्धांत को ध्यान से जानने का प्रयास करना चाहिए और अपने तर्कों का समर्थन करने के लिए इस न्यायालय द्वारा विचाराधीन प्रश्नों के संदर्भ से अलग किए गए निर्णय से शब्दों या वाक्यों को नहीं चुनना चाहिए। ..."

54. *इस संदर्भ में, हम अंबिका क्वारी वर्क्स बनाम गुजरात राज्य और अन्य में न्यायालय द्वारा कही गई बात को दोहराते हैं:*

"18. ... किसी भी निर्णय का अनुपात उस मामले के तथ्यों की पृष्ठभूमि में समझा जाना चाहिए। यह बहुत पहले कहा गया है कि एक मामला केवल इस बात के लिए एक अधिकार है कि वह वास्तव में क्या निर्णय लेता है, न कि यह कि उससे क्या तार्किक रूप से निकलता है। (क्विन बनाम लेथम में लॉर्ड हेल्सबरी देखें)। ...""

इसके बाद, ***रोजर शशौआ*** (उपर्युक्त) में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैराग्राफ संख्या में अपनी टिप्पणी दर्ज की। 55, जो इस प्रकार है:-

*"**55.** उपर्युक्त अधिकारियों से, यह स्पष्ट है कि किसी निर्णय के अनुपात का पूर्ववर्ती मूल्य होता है और न्यायालय के लिए यह अनिवार्य है कि वह उसमें प्रस्तुत तथ्यों और उस संदर्भ के संबंध में निर्णय पर विचार करे जिसमें प्रश्न उठे थे और कानून घोषित किया गया है। निर्णय को संपूर्णता में पढ़ना भी आवश्यक है और यदि कोई सिद्धांत निर्धारित किया गया है, तो उस पर मामले में विचार के लिए उठे प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाना चाहिए। किसी से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वह संदर्भ से हटकर निर्णय से कोई शब्द या वाक्य उठाए और पूर्ववर्ती मूल्य वाले अनुपात को समझे। इसके अलावा, जिस न्यायालय के समक्ष कोई अधिकारी उद्धृत किया जाता है इसमें जो निर्णय लिया गया है, उस पर विचार करना आवश्यक है, लेकिन न्याय-तर्क प्रक्रिया का अनुसरण करके जो निष्कर्ष निकाला जा सकता है, उस पर विचार नहीं करना आवश्यक है। "*

15. प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने यह मुद्दा उठाया कि मूल डिक्री धारक की मृत्यु बहुत पहले हो गई थी और उसे प्रतिस्थापित नहीं किया गया था और यहां तक कि निर्णय ऋणी की मृत्यु मूल डिक्री धारक की मृत्यु से पहले हो गई थी और उसे भी प्रतिस्थापित नहीं किया गया था, और इसलिए, निहितार्थ से इजराई कार्यवाही समाप्त हो गई। मुझे डर है कि यह कानून का सही अर्थ नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***वी. उथिरपति बनाम अशरब अली और अन्य*** के मामले में ***(1998) 3 एससीसी 148*** में रिपोर्ट किया कि इजराई कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान डिक्री धारक या निर्णय ऋणी की मृत्यु के कारण, इजराई कार्यवाही समाप्त नहीं होगी बल्कि लंबित रहेगी। इसने आगे कहा कि इजराई आवेदन को डिक्री धारक के कानूनी प्रतिनिधियों की पीठ पीछे चूक के लिए भी खारिज नहीं किया जा सकता है। पैराग्राफ नं. ***वी. उथिरापथी*** (उपर्युक्त) के 13 और 14 काफी उपयुक्त हैं और संदर्भ के लिए उद्धृत किए गए हैं:-

*"**13.** वेंकटचलम चेट्टी बनाम रामास्वामी सेरवाई [1932 आईएलआर 55 मैड. 352 = एआईआर 1932 मैड. 73 (एफबी)] में, मद्रास उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ ने माना है कि यह नियम अधिनियमित करता है कि दुष्प्रेरण का दंड इजराई कार्यवाही से जुड़ी नहीं होगी। सीपीसी पर मुल्ला की टिप्पणी (खंड 3) पृष्ठ 2085 (15 वां संस्करण, 1997) उच्च न्यायालय के कई निर्णयों का संदर्भ देता है:*

> *"नियम 12 में एक छूट दी गई है जो यह प्रावधान करती है कि जहां इजराई कार्यवाही के किसी पक्षकार की उसके लंबित रहने के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो दुष्प्रेरण के प्रावधान लागू नहीं होते*

हैं। इसलिए यह नियम डिक्री धारक के लाभ के लिए है, क्योंकि उसके उत्तराधिकारियों को नियम 2 के तहत प्रतिस्थापन के लिए कदम उठाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वे कार्यवाही जारी रखने के लिए तुरंत या किसी भी समय आवेदन कर सकते हैं या वे नया इजराई आवेदन दायर कर सकते हैं। "

***14.** हमारी राय में, सीपीसी पर मुल्ला की टिप्पणी में कानून का उपरोक्त कथन इजराई कार्यवाही में पक्षों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और सिविल कोर्ट की शक्तियों से संबंधित कानूनी स्थिति को सही ढंग से दर्शाता है। "*

16. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि डिक्री धारक की मृत्यु और उसके कानूनी प्रतिनिधियों के रिकॉर्ड पर न आने या निर्णय ऋणी की मृत्यु और उसके कानूनी प्रतिनिधियों के रिकॉर्ड पर न आने के बाद इजराई याचिका में कोई कमी नहीं की जा सकती। डिक्री धारक के कानूनी प्रतिनिधियों के लिए यह भी खुला है कि वे डिक्री धारक की मृत्यु के मामले में एक नई इजराई याचिका दायर करें या निर्णय ऋणी की मृत्यु के मामले में, डिक्री धारक निर्णय ऋणी के कानूनी प्रतिनिधियों को पक्षकार बनाते हुए एक नई इजराई याचिका दायर कर सकता है।

17. इसलिए, मुझे प्रतिवादियों के विद्वान वकील द्वारा डिक्री धारक या निर्णय ऋणी की मृत्यु के संबंध में विद्वान इजराई न्यायालय के समक्ष कार्यवाही को गलत बनाने संबंधी दलील में कोई योग्यता नहीं दिखती।

18. विद्वान ट्रायल कोर्ट के समक्ष विपक्षी पक्षों/प्रतिवादियों द्वारा उठाए गए आधारों में से एक प्रावधान का गलत उल्लेख था। विद्वान ट्रायल कोर्ट ने इसे यह कहते हुए खारिज कर दिया कि आवेदन के गलत शीर्षक का उल्लेख मात्र आवेदन को खारिज करने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता क्योंकि यह अति-तकनीकी दृष्टिकोण होगा। हालांकि, इसने संहिता के आदेश 21 नियम 106(1) के तहत दायर बहाली के लिए आवेदन पर विचार किया और उसके बाद संहिता के आदेश 21 नियम 106(3) के तहत सीमा के मुद्दे पर चर्चा की और कहा कि सीमा को माफ नहीं किया जा सकता क्योंकि सीमा अधिनियम की धारा 5 संहिता के आदेश 21 नियम 106 के तहत दायर याचिका पर लागू नहीं होती है और ***एस.पोन्नुपांडियन*** (उपर्युक्त) और ***दामोदरन पिल्लई और अन्य*** के मामलों पर भरोसा किया। (उपर्युक्त) जिसमें यह माना गया है कि यदि चूक के लिए आवेदन को खारिज करने का आदेश पारित किया गया है, तो इसकी बहाली के लिए आवेदन उक्त आदेश की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर दायर किया जाना चाहिए, उसके बाद नहीं।

लेकिन यहां पहले की गई चर्चा के प्रकाश में, यह स्पष्ट है कि इजराई कार्यवाही गलत तरीके से खारिज कर दी गई थी और यह भी स्पष्ट है कि मामले के वर्तमान तथ्यों और परिस्थितियों में संहिता के आदेश 21 नियम 106 का कोई आवेदन नहीं हो सकता है। जैसा कि पहले ही चर्चा की गई है कि यदि संहिता का आदेश 21 नियम 106 लागू नहीं होता है, तो बहाली आवेदन दाखिल करने के लिए 30 दिनों की सीमा लागू नहीं होगी और इसलिए, याचिकाकर्ता द्वारा दायर याचिका को संहिता की धारा 151 के तहत दायर की गई याचिका के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, न कि संहिता के आदेश 21 नियम 106 के तहत। इसलिए, विद्वान ट्रायल कोर्ट के समक्ष विविध मामले को संहिता की धारा 151 के तहत माना जाना चाहिए था, लेकिन विद्वान ट्रायल कोर्ट इस बिंदु को पूरी तरह से भूल गया।

19. इसलिए, पिछले पैराग्राफ में चर्चा की गई विधि के आलोक में और वर्तमान मामले में के तथ्यों पर इसे लागू करते हुए, मुझे यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि विद्वान उप न्यायाधीश ने विवादित आदेश पारित करने में अधिकार क्षेत्र की त्रुटि की है। इसलिए, विद्वान उप न्यायाधीश-द्वितीय, दानापुर द्वारा, विविध वाद संख्या 54/2017 में दिनांक 22.11.2023 को पारित किया गया विवादित आदेश अपास्त किया जाता है।

20. हालाँकि, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि इजराई का वाद वर्ष 1991 का है, जिसे चूक में खारिज कर दिया गया था और 2017 में इसकी पुनर्स्थापना हेतु विविध वाद दायर किया गया था, मुझे नहीं लगता कि वाद को विद्वान अधीनस्थ न्यायाधीश को नए सिरे से विचार के लिए भेजने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा होगा। जैसा कि दिनांक 24.03.2017 आदेश है, जिसमें इजराई वाद संख्या 07/1991 चुक के कारण खारिज कर दिया गया था, एक अवैध आदेश था, विविध वाद संख्या 54/2017 की अनुमति है और इजराई वाद संख्या 07/1991 में दिनांक 24.03.2017 को पारित आदेश को अपास्त किया जाता है।

21. तदनुसार, वर्तमान याचिका को उपर्युक्त आदेश के संदर्भ में अनुमति दी गई है।

(अरुण कुमार झा,न्यायमूर्ति)

बालमुकुन्द/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक,

कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।